Port Officers have been alerted to examine the imported consignment with greater vigil to ensure that the necessary labelling requirements are printed or affixed on each strip before clearing the consignments.

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निजी चिकित्सक

223. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सभी सरकारी प्रयासों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के खाली पदों को भरा नहीं जा सकता है;

(ख) क्या सरकारी चिकित्सकों के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में रुचि न लेने के फलस्वरूप सरकार निजी चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में जनता का इलाज करने हेतु नियुक्त करने पर विचार कर रही है;

(ग) इससे सरकार को प्रतिवर्ष कुल कितना अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा; और

(घ) क्या सरकार ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए वर्तमान डाक्टरी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके हाई स्कूल पास बच्चों को तीन वर्षीय "डाक्टरी-डिप्लोमा" का नया कोर्स चालू करने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की नियुक्ति और तैनाती संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं। तथापि केन्द्र को इस बात का पता है कि इन केन्द्रों में डाक्टरों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) हाल ही में शुरू किए गए प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन मानदेय के भुगतान के आधार पर महीने में दो बार नियत दिवसों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सीय गर्भ समापन, प्रसव पूर्व परिचर्या और प्रसवोतर परिचर्या तथा अन्य प्रसव परिचर्या संबंधी सेवायें प्रदान करने के लिए संविदा के आधार पर डाक्टरों अधिमानत: लेडी डाक्टरों की सेवायें उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

(ग) नौवीं योजना अवधि के लिए इस उद्देश्य के लिए 47.65 करोड रुपये का कुल प्रावधान रखा गया है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Briefing MPs about the problem of AIDS

224. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government intend to organise a sensitisation programme for Members of Parliament in order to breif them about the problem of AIDS;

(b) if so, whether the programme would begin on 1st December, 1997 which is the World AIDS Day or thereabout;

(c) what would be the structure of the programme; and

(d) whether there has already been a delay in organising such a programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) to (d) It was inter-alia decided in the last National AIDS Committee meeting that Members of Parliament and Legislative Assemblies would be involved in advocacy campaigns and in the AIDS awareness programme. For this purpose a sensitisation programme for Members of Parliament is being drawn up but the details will take some more time to be finalised.